



CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड
न्यूजपेपर एनालिसिस



स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

चाणक्य वीकली करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस
Web: www.chanakyaiasacademy.com, Email: enquiry@chanakyaiasacademy.com
Toll Free No. 1800 - 274 - 5005

एसएसएलवी वाहन की विफलता

संदर्भ :

- एसएसएलवीडी1/ईओएस2 मिशन की पहली विकासात्मक उड़ान पेलोड (उपग्रहों) को उनकी आवश्यक कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रही, और इसके साथ उपग्रह, जो पहले से ही प्रक्षेपण यान से अलग हो गया था, वह खो गया।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) डी1/ईओएस2 मिशन दो उपग्रहों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 (ईओएस2) और आजादीसैट को ले जा रहा था।

मिशन का उद्देश्य

- इस मिशन का उद्देश्य दो उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 350 किमी की ऊंचाई पर वृत्ताकार निम्न-पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करना था। ईओएस-2 जिसे इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, उन्नत ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन की पेशकश करता था।
 - यह इन्फ्रारेड क्षेत्र में संचालित होता और जलवायु अध्ययन के लिए इमेजिंग से लेकर पृथ्वी पर नजर रखने तक कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता था।
- दूसरी ओर, आजादीसैट, लगभग 50 ग्राम वजन वाले 75 छोटे पेलोड का एक समूह था, जिसे छालों द्वारा एकीकृत किया गया था।
 - इसने छोटे-छोटे प्रयोग किए जो इसकी कक्षा में आयनकारी विकिरण को मापता है और एक ट्रांसपोंडर भी है जो ऑपरेटर्स को इसे एक्सेस करने में सक्षम बनाने के लिए हैम रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करता है।

यह कहाँ विफल हुआ

- एसएसएलवी ठोस ईंधन द्वारा संचालित तीन चरणों से बना था और इन तीनों ने योजना के अनुसार अपना कार्य किया।
- हालांकि, जब यह उस स्तर पर आया जहाँ उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना था, तो एक गड़बड़ी हुई जिसके परिणामस्वरूप उपग्रह हमेशा के लिए खो गए।

वृत्ताकार और अण्डाकार कक्षाओं के बीच अंतर:

- अधिकतर वस्तुओं जैसे उपग्रह और अंतरिक्ष यान को अण्डाकार कक्षाओं में केवल अस्थायी रूप से रखा जाता है। फिर उन्हें या तो अधिक ऊंचाई पर गोलाकार कक्षाओं में धकेल दिया जाता है या त्वरण तब तक बढ़ा दिया जाता है जब तक कि प्रक्षेपवक्र एक दीर्घवृत्त से अतिपरवलय में परिवर्तित नहीं हो जाता है और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच जाता है - उदाहरण के लिए, चंद्रमा या मंगल या उससे भी अधिक दूर।
- पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अधिकतर वृत्ताकार कक्षाओं में रखा जाता है। एक कारण यह है कि यदि उपग्रह का उपयोग पृथ्वी की इमेजिंग के लिए किया जाता है, तो पृथ्वी से एक निश्चित दूरी होने पर यह आसान हो जाता है। यदि दूरी एक अण्डाकार कक्षा की तरह बदलती रहती है, तो कैमरों को केंद्रित रखना जटिल हो सकता है।

उपग्रह क्यों खो गए?

- यदि पृथ्वी से निकटतम दूरी केवल 76 किमी है, जैसा कि इस बार हुआ, तो उस ऊंचाई पर वस्तु द्वारा एक वायुमंडलीय खिंचाव का अनुभव होता है।
- इसके बाद, जब तक कर्षण या खिंचाव को दूर करने के लिए पर्याप्त जोर नहीं लगाया जाता, तब यह गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचाई खो देता है और पृथ्वी की ओर गिर जाता है और अंततः घर्षण के कारण जल जाता है।

लॉन्च में क्या गलत हुआ?

- आज रॉकेट तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यदि रॉकेट का मार्ग अपने नियोजित मार्ग से बदल रहा है, तो भी ऐसे सेंसर भी होते हैं जो इस जानकारी को सिस्टम को वापस फीड करेंगे।
- यह तुरंत मार्ग सुधार को चालू करेगा जो रॉकेट के प्रक्षेपवक्र को पुनर्स्थापित करेगा।
- भले ही एक या दो सेंसर विफल हो जाएं, फिर भी कुछ अन्य सेंसर होंगे जो मार्ग सुधार को प्रभावित करेंगे।

लॉन्च वाहन:

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी):

- हाल ही में इसरो छोटे पेलोड को लॉन्च करने के लिए एसएसएलवी को पीएसएलवी से अधिक कुशल बनाकर इसका उपयोग कर रहा है। अब, 500 किलोग्राम तक द्रव्यमान वाले पेलोड को पीएसएलवी के बजाय एसएसएलवी का उपयोग करके भेजा जा सकता है।
- एसएसएलवी को पीएसएलवी के बाद इसरो के अगले वर्कहॉर्स रॉकेट के रूप में पदोन्नत किया गया है।
- केवल 2 मीटर व्यास और 35 मीटर की ऊंचाई के साथ, यह वास्तव में पीएसएलवी से छोटा है जिसका उपयोग व्यापक श्रेणी के उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया गया है।

एसएसएलवी के लाभ:

- एसएसएलवी आसानी से छोटे से मध्यम भार को 10 किग्रा से 500 किग्रा तक ले जा सकता है। यह कम खर्चीला भी होता है।
- ठोस ईंधन द्वारा संचालित तीन चरणों का एक और फायदा है। ठोस ईंधन को संभालना आसान होता है, जबकि पीएसएलवी और जीएसएलवी में प्रयुक्त तरल प्रणोदकों को संभालना अधिक जटिल होता है।
- एसएसएलवी में कई उपग्रहों को लॉन्च करने की सुविधा है, और मांग पर उपग्रहों को लॉन्च किया जा सकता है - क्योंकि रॉकेट को न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। ये सभी विशेषताएं इसे वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए बहुत आकर्षक बनाती हैं।

पीएसएलवी:

- यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसे 'इसरो का वर्कहॉर्स' कहा जाता है।

इस प्रक्षेपण यान में कुल 4 चरण हैं:

- पहला चरण - PSLV S139 सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करता है जिसे 6 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर द्वारा संवर्धित किया जाता है।
- दूसरा चरण - पीएसएलवी अपने दूसरे चरण के लिए एक पृथ्वी भंडारण योग्य तरल रॉकेट इंजन का उपयोग करता है, जिसे विकास इंजन के रूप में जाना जाता है, जिसे तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
- तीसरा चरण - यह एक ठोस रॉकेट मोटर है जो प्रक्षेपण के वायुमंडलीय चरण के बाद ऊपरी चरणों को उच्च जोर प्रदान करती है।
- चौथा चरण - पीएसएलवी का सबसे ऊपरी चरण जिसमें दो पृथ्वी भंडारण योग्य तरल इंजन शामिल हैं।

भार क्षमता:

- सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं (एसएसपीओ) (ऊंचाई - 600 किलोमीटर) के लिए 1750 किग्रा।
- जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स (जीटीओ) के लिए 1425 किग्रा।

जीएसएलवी:

- भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है। यह चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।

इसके तीन चरण हैं:

- पहला चरण - 138 टन के सॉलिड रॉकेट मोटर को 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन द्वारा संवर्धित किया गया है।
- दूसरा चरण - जीएसएलवी के दूसरे चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है।
- तीसरा चरण - क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट (सीयूएसपी) के तहत विकसित, सीई-7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है।

LAUNCH SERVICES AT A GLANCE

The Small Satellite Launch Vehicle or SSLV made for the launch within one week by six people

THE SPECIFICS	SSLV	PSLV	GSLV MK-II	GSLV MK-III
Height	34m	44m	49.13m	43.43m
Diameter	2m	2.8m	2.8m	4m
Number of stages	three	four	three	three


Payload carrying capacity

SSLV | 500kg to low earth orbit

GSLV MK-II | 2500kg to geosynchronous transfer orbit and 5000kg to low earth orbit

PSLV | 1,750kg to 600km sun-synchronous polar orbit and 1,425kg to sub-geosynchronous transfer orbit

GSLV MK-III | Four tonnes into geosynchronous transfer orbit or around 10 tonnes to low earth orbit



SET TO SOAR: The SSLV is set to go on its maiden flight on Sunday

इसमें चार लिक्विड-इंजन स्टैप-ऑन भी हैं।

भार क्षमता:

- जीटीओ के लिए संचार उपग्रहों के 2500 किलोग्राम इन्सैट वर्ग
- LEO में कई छोटे उपग्रहों के लिए 5000 किलोग्राम तक के भारी उपग्रह।

पृथ्वी की कक्षाएँ

1. Geostationary Earth Orbit

- इसे जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कहा जाता है।
- यह एक कम झुकाव वाली कक्षा है।
- इसमें रखे गए उपग्रह 'स्थिर' दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी एक कक्षीय अवधि होती है जो पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान होती है। इसलिए, उपग्रह/अंतरिक्ष यान प्रत्येक दिन एक ही समय पर आकाश में एक ही बिंदु पर लौटता है।
- संचार उपग्रहों को अक्सर GEO में रखा जाता है।
- भू उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सीधे ऊपर की ओर होते हैं। एक प्रेक्षक को जो ध्रुव के निकट है, वे आकाश में नीचे की ओर दिखाई देंगे।
- इसरो की भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली [इन्सैट] को इसी में रखा गया है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है।

2. Low Earth Orbit (LEO)

- यह अन्य कक्षाओं की तुलना में पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब है।
- पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 160 किमी से 1000 किमी के बीच हो सकती है।
- LEO में रखे गए उपग्रहों में एक झुका हुआ तल हो सकता है।
- यह आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कक्षाओं में से एक है, क्योंकि इसमें रखे गए उपग्रहों के पास अधिक उपलब्ध मार्ग हैं क्योंकि उन्हें GEO के रूप में पृथ्वी के चारों ओर किसी विशेष पथ का अनुसरण नहीं करना पड़ता है।
- इसका उपयोग उपग्रह इमेजिंग के लिए किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) LEO का उपयोग करता है [यह अंतरिक्ष यानियों की यात्रा को आसान बनाता है]
- इसका उपयोग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा किया जाता है।

3. मध्यम पृथ्वी की कक्षा (MEO)

- जिस कक्षा की ऊंचाई LEO और GEO के बीच होती है, उसे मध्यम पृथ्वी की कक्षा के रूप में जाना जाता है।
- इसे इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है।
- यह LEO के साथ समानता साझा करता है क्योंकि MEO उपग्रहों को भी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के साथ पथ को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- नेविगेशन उपग्रह और कई कृत्रिम उपग्रहों को एमईओ में रखा गया है।
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को एमईओ (20200 किमी) में रखा गया है
- संचार उपग्रह भी यहां रखे जा सकते हैं।

4. ध्रुवीय कक्षा और सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)

- एसएसओ उपग्रह पृथ्वी के उपर पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं।
- ये मोटे तौर पर पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं।
- ऊंचाई 200कि.मी. जितनी कम हो सकती है, हालांकि ज्यादातर उपग्रह 600-800 किमी के बीच रखे जाते हैं।
- जैसा कि नाम से पता चलता है, एसएसओ उपग्रह सूर्य के साथ तालमेल बिठाते हैं। [अर्थ - सूर्य के सापेक्ष स्थिति 'स्थिर' है।]
- SSO उपग्रह हमेशा उसी स्थान पर उसी स्थानीय समय पर जाते हैं जब वे सूर्य-तुल्यकालिक होते हैं।
- इसका उपयोग इमेजिंग, जासूसी और मौसम उपग्रहों के लिए किया जाता है।

5. जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ)

- इस कक्षा का उपयोग उपग्रहों द्वारा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए किया जाता है। यह LEO और GSO के बीच ट्रांसफर ऑर्बिट है।
- जीटीओ उपग्रहों को उनके गंतव्य कक्षा में स्थापित करने से पहले एक पड़ाव [मध्यवर्ती चरण] प्रदान करता है। इस तरह, यह बिल्ट-इन मोटर्स से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उपयोग करता है।
- प्रमोचकों को सीधे GEO में उपग्रह लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह पहले जीटीओ का उपयोग कर सकता है।
- यह एक अत्यधिक विलक्षण कक्षा है।

उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में सूखे का कहर

संदर्भ :

- हाल के दिनों में, झारखंड और उत्तर प्रदेश सदी के सबसे खराब मानसून के मौसम का सामना कर रहे हैं।
- पिछले 122 वर्षों में उत्तर प्रदेश और झारखंड में इतनी खराब मानसूनी बारिश कभी नहीं हुई।

झारखंड:

- जून और अगस्त के बीच, झारखंड में वर्षा 371.9 मिमी दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 627.6 मिमी होती है, इस वर्ष वर्षा में 41 प्रतिशत की मौसमी कमी थी।
- भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 1901 के बाद से झारखंड (जून से अगस्त) में दर्ज की गई यह अब तक की सबसे कम वर्षा है।
- पिछले 122 वर्षों में केवल दो बार झारखंड में इतनी कम बारिश हुई है।

उत्तर प्रदेश:

- उत्तर प्रदेश के लिए भी, तस्वीर गंभीर है, क्योंकि राज्य ने 449.1 मिमी (जून से अगस्त) के मौसमी औसत का केवल 251.7 मिमी वर्षा दर्ज किया है।
- यूपी इस साल सबसे अधिक बारिश की कमी वाला राज्य है और झारखंड की तरह मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से ऐसा ही बना हुआ है।

बिहार :

- ओवरफ्लो होने वाली गंगा और बाढ़ के मानदंड से हटकर, 2022 का मानसून बिहार के लिए सामान्य रहा है। चालू मौसम के दौरान, बिहार में 12 अगस्त तक सामान्य के 602.6 मिमी की तुलना में 376.5 मिमी की बारिश रही। इस प्रकार 38 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई है।
- 2022 का मानसून बिहार का सबसे खराब हो सकता है - इससे पहले केवल एक बार, 1972 में, राज्य को जून से अगस्त के दौरान 375 मिमी बारिश हुई थी।

लंबी अवधि के मानसून के रुझान

- झारखंड: जुलाई और अगस्त में मानसून के मौसम में सबसे अधिक वर्षा क्रमशः 31 प्रतिशत और 28 प्रतिशत होती है। राज्य की वार्षिक वर्षा का 84 प्रतिशत जून और सितंबर के बीच होता है।
- उत्तर प्रदेश: मानसून की 34 प्रतिशत मौसमी वर्षा जुलाई में और 31 प्रतिशत अगस्त में होती है। वार्षिक वर्षा का 89 प्रतिशत जून से सितंबर के महीनों के दौरान प्राप्त किया जाता है।
- बिहार: बिहार की 33 प्रतिशत मानसूनी वर्षा जुलाई में होती है और 28 प्रतिशत अगस्त में होती है। वार्षिक वर्षा का 85 प्रतिशत से अधिक जून और सितंबर के बीच होता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक वर्षा होती है।

NORMAL MONSOON RAINFALL (MM) OVER JHARKHAND, BIHAR, UP

STATE	JUNE	JULY	AUGUST	SEPT	JUNE-SEPT
Jharkhand	190.3	313.9	289.2	225.7	1,019.1
Uttar Pradesh	96.1	238.6	219	142.9	696.7
Bihar	160.2	313.9	264.5	200.1	938.7

वर्षा की कमी के कारण:

- बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणाली:
 - इस मौसम में, बंगाल की खाड़ी में केवल तीन निम्न दाब प्रणालियां विकसित हुईं, जो ज्यादातर ओडिशा के तट से दूर हैं।
 - इनमें से किसी भी प्रणाली ने झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार को प्रभावित नहीं किया।
 - इस प्रकार, बारिश के दो कारणों में से एक इन राज्यों के पक्ष में नहीं रहा।

मानसून टूफ(monsoon trough):

- इसके अलावा इस साल मानसून टूफ -
 - एक पूर्व-पश्चिम निम्न दबाव का क्षेत्र, जो पाकिस्तान के ऊपर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक फैला हुआ है, जुलाई और अगस्त में अधिकांश दिनों तक अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बना रहा।

ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों ने पूरे मौसम में उच्च वर्षा की कमी में योगदान दिया।

आगे का रास्ता

- देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में खाद्य और पानी की कमी वास्तविक मुद्दा होने जा रहे हैं, जिससे इस वर्ष भारत के खरीफ उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में कृषि मौसम विभाग ने धान की रोपाई करने की सलाह दी है और कम अवधि के चावल की किस्मों के उपयोग का सुझाव दिया है।
 - विशेषज्ञों ने लाल चने की खेती को प्रोत्साहित किया है।
 - किसानों को अंतर-फसल का विकल्प चुनने की भी सिफारिश की जाती है।

झारखंड में किसानों के लिए कृषि बैठक में मिट्टी में नमी के संरक्षण के उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है।

- लगातार कम से कम तीन दिनों तक 50 से 60 मिमी बारिश और पर्याप्त नमी होने तक बुवाई की सलाह नहीं दी जाती है।
- कम अवधि के चावल, बाजरा, मक्का और अरहर की खेती बाकी मौसम में की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में एनडीएम अधिनियम पारित किया गया था।

उद्देश्य:

- यह एक राष्ट्रीय कानून है जो केंद्र सरकार को पूरे देश या उसके हिस्से को आपदा से प्रभावित घोषित करने और आपदा के "जोखिमों और प्रभावों" को कम करने के लिए शमन की योजना बनाने का अधिकार देता है।

नोडल प्राधिकरण

- अधिनियम समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
- चार महत्वपूर्ण संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है:
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए): इसे आपदा प्रबंधन नीतियों को निर्धारित करने और समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
 - राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी): यह भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों से बनी होती है जिन्हें एनडीएमए की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम): यह प्राकृतिक प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए एक संस्थान है।
 - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ): यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं से संबंधित विशेष प्रतिक्रिया/कार्य के लिए बुलाया जाता है।

राज्य और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन

- अधिनियम अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार राज्य और जिला स्तर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का भी प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में वित्तीय तंत्र के प्रावधान शामिल हैं जैसे कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए धन का निर्माण, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राज्य -जिला स्तर पर इसी तरह की निधि का प्रावधान है।

कवरेज

- इसमें सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है जो एक समुदाय के मुकाबला करने की क्षमता से परे हैं।

सज़ा

- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत, आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले को एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
- यदि इस इनकार से लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।

श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर एक चीनी पोत का विवादास्पद दौरा

संदर्भ :

- हाल ही में एक चीनी “बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रेकिंग जहाज” श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित हंबनटोटा बंदरगाह आया ।
- भारत द्वारा उठाए गए चिंताओं के बाद श्रीलंका ने चीन को हाई-टेक पोत के आगमन को स्थगित करने के लिए कहा था, लेकिन हाल ही में श्रीलंका ने इस डॉकिंग के लिए मंजूरी दे दी ।
- हंबनटोटा बंदरगाह एक व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक परियोजना है जिसे पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने अपने गृह जिले में चीन की सहायता से बनाया था, जिसे राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे की सरकार को 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के खिलाफ 2017 में 99 साल के पट्टे पर चीन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे वे चुकाने में असमर्थ थे ।
- श्रीलंका ने भी बंदरगाह के आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चीनी को सौंप दिया । श्रीलंकाई अधिकारियों ने उस समय कहा था कि चीन पर उनका कुल कर्ज करीब 8 अरब डॉलर है ।

पोत के बारे में

- “युआन वांग 5” को श्रीलंकाई सरकार द्वारा “वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज” के रूप में वर्णित किया गया था । BRISL कोलंबो स्थित एक संगठन (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका) के अनुसार, , युआन वांग 5 “हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में उपग्रह नियंत्रण और अनुसंधान ट्रेकिंग” का संचालन करेगा ।
- कहा जाता है कि युआन वांग वर्ग के जहाजों का इस्तेमाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स द्वारा उपग्रह के साथ-साथ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर नज़र रखने और समर्थन करने के लिए किया जाता है ।

भारत की प्रतिक्रियाएँ:

- भारत ने चीनी पोत की यात्रा पर अपनी चिंता व्यक्त की है । विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत “अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर डालने वाले किसी भी विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी करता है” और बाद में उन आक्षेपों को खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीलंका दबाव में था ।
- भारत द्वारा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ इस मामले को उठाए जाने के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कंबोडिया में हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी के साथ इस मुद्दे को उठाया ।

चीनी जवाब

- भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बाद से चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, श्रीलंका ने चीन से “आगे के परामर्श की आवश्यकता के आलोक में” जहाज की यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया । चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने प्रासंगिक रिपोर्टों को नोट कर लिया है और वह दो बिंदुओं पर जोर देना चाहेगा ।
- पहला, श्रीलंका हिंद महासागर में एक परिवहन केंद्र है । चीन सहित विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान जहाजों ने पुनःपूर्ति के लिए श्रीलंका में पोर्ट कॉल किए हैं ।
 - चीन हमेशा कानून के अनुसार ऊंचे समुद्रों की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पानी में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों पर तटीय देशों के अधिकार क्षेत्र का पूरी तरह से सम्मान करता है ।
- दूसरा, श्रीलंका एक संप्रभु देश है । इसे अपने विकास हितों के आधार पर अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करने का अधिकार है ।
- सामान्य सहयोग करना हमारे दोनों देशों द्वारा किया गया स्वतंत्र विकल्प है । यह दोनों पक्षों के साझा हितों की सेवा करता है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है ।” सीधे भारत का जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा कि “कुछ देशों के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित ‘सुरक्षा चिंताओं’ का हवाला देना पूरी तरह से अनुचित था ।”

श्रीलंका का पक्ष

- श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्रालय ने कहा: “सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद, चीनी जनवादी गणराज्य के दूतावास को जहाज के स्थगित आगमन के लिए मंजूरी दे दी गई थी।”
- घोषणा का मतलब था कि विवादास्पद पोत याला, जो पहले 11 अगस्त के लिए निर्धारित थी, को प्रभावी रूप से पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जबकि इसकी सप्ताह भर की अवधि पहले की योजना के अनुसार बनी रही।
- इसने अपने बयान में भारत का नाम लिए बिना कहा की यह घटनाक्रम “मंत्रालय के साथ उठाई गई कुछ चिंताओं के आलोक में” था।
- श्रीलंका ने कहा कि यू.एस. और भारतीय दूतों को उनकी आपत्तियों के लिए “ठोस कारण” प्रदान करने के लिए कहा गया था।
- “चीनी जहाज को प्रवेश से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारणों से संतुष्ट नहीं होने के कारण, सरकार ने कोलंबो में चीनी दूतावास को सूचित करने का फैसला किया कि जहाज को हंबनटोटा की यात्रा जारी रखने के लिए सूचित किया जाए,”



संक्षेप में :

- 13 अगस्त को, श्रीलंका ने अपने चीनी-वित्त पोषित हंबनटोटा बंदरगाह पर एक चीनी उपग्रह-ट्रैकिंग पोत के आगमन को मंजूरी दी।
- भारत ने चीनी पोत की यात्रा पर अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी की कि भारत "अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर डालने वाले किसी भी विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी करता है"।
- पोत याला को स्थगित करने के लिए कहे जाने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीधे भारत का जिक्र किए बिना, चीन ने कहा कि "कुछ देशों के लिए श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए तथाकथित 'सुरक्षा चिंताओं' का हवाला देना पूरी तरह से अनुचित था।"

हंबनटोटा बंदरगाह के बारे में:

- यह श्रीलंका के दक्षिणी सिरे में एक गहरे पानी का बंदरगाह है।
- हंबनटोटा बंदरगाह, जिसे मगमपुरा महिंदा राजपक्षे बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, श्रीलंका के हंबनटोटा में स्थित एक समुद्री अंतर्देशीय बंदरगाह है। इसका निर्माण श्रीलंकाई बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा किया गया है और ज्यादातर चीन के एक्जिम बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
- हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण 15 जनवरी 2008 को शुरू हुआ। चीनी कंपनियां, सिनोहाइड्रो कॉर्पोरेशन और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी निर्माण के पहले चरण में शामिल थीं, जिसकी अनुमानित लागत बंकर टर्मिनल के लिए \$76.5 मिलियन को छोड़कर \$360 मिलियन थी।
- चीनी सरकार ने 85% फंडिंग प्रदान की जबकि श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने शेष फंडिंग प्रदान की।

रोहिंग्याओं पर भारत की नीति

संदर्भ :

- हाल ही में केंद्रीय आवास मंत्री ने ट्वीट किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए बने फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा, और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- मंत्री ने कहा “भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 का सम्मान करता है और उसका पालन करता है और सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है।”
- हालाँकि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि “रोहिंग्या अवैध शरणार्थियों/विदेशियों” को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

- रोहिंग्या एक जातीय समूह है जिसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं जो पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत से हैं, उनकी भाषा बंगाली है।
- म्यांमार ने उन्हें "विदेशी निवासी" या "सहयोगी नागरिक" के रूप में वर्गीकृत करता है।
- हिंसा की कई लहरों के बाद, जो पहली बार 2012 में शुरू हुई थी, उन्हें बड़ी संख्या में म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
- म्यांमार की सेना ने 2017 में हमलों को फिर से शुरू किया और लाखों रोहिंग्या ने बांग्लादेश में शरण ली।

निर्वासन की प्रक्रिया

- गृह मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट अधिनियम, 1920 या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत अवैध अप्रवासियों का पता लगाया जाता है, और उन्हें हिरासत में लेने के बाद निर्वासित किया जाता है।
- उनकी पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के अधिकार भी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपे गए हैं।
- एक बार जब एक 'विदेशी' को बिना किसी दस्तावेज के अवैध रूप से रहने के लिए पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है।
- आरोपी के दोषी पाए जाने पर तीन महीने से आठ साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
- उनकी सजा पूरी करने के बाद, अदालत निर्वासन का आदेश देती है।
- विदेशी कैदियों को तब तक हिरासत केंद्रों में ले जाया जाता है जब तक कि मूल देश उन्हें सत्यापित और स्वीकार नहीं कर लेता।

निर्वासित रोहिंग्या

- 2018 में, सात रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजा गया था।
- यह पहली बार था कि म्यांमार ने सात रोहिंग्याओं को पहचान का प्रमाण पत्र जारी किया।
- ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के अनुसार, अक्टूबर 2018 से, भारत ने 12 रोहिंग्याओं को म्यांमार में निर्वासित कर दिया है, "यह दावा करते हुए कि वे स्वेच्छा से चले गए"।
- दिसंबर 2017 में, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या हैं। इनमें से केवल 16,000 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के साथ पंजीकृत बताए जाते हैं।

भारत की शरणार्थी नीति

- भारत में शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद उनकी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है।
- विदेशी अधिनियम, 1946, एक वर्ग के रूप में शरणार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। यह केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने की बेलगाम शक्ति भी देता है।
- इसके अलावा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर करता है और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए केवल हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- इसके अलावा, भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल में भी शामिल नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं।
- 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं होने के बावजूद, भारत का शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत में विदेशी लोगों और संस्कृति को आत्मसात करने की नैतिक परंपरा है।
- इसके अलावा, भारत का संविधान भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जबकि सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशी नागरिकों सहित अन्य व्यक्ति समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के हकदार हैं।"

1951 शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए भारत का तर्क

- 1951 के सम्मेलन में शरणार्थियों की परिभाषा केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, यह व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों से संबंधित नहीं है।
- यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शरणार्थी की परिभाषा में शामिल किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से विकसित दुनिया पर एक बड़ा बोझ होगा।
- दूसरी ओर, यदि यह तर्क दक्षिण एशिया के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो भारत के लिए भी एक समस्यात्मक प्रस्ताव हो सकता है।

शरणार्थियों पर कानून की आवश्यकता



दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान:

- भारत में अक्सर शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या रही है।
- इसलिए, एक दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान के लिए आवश्यक है कि भारत एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाकर अपने धर्मार्थ दृष्टिकोण से हटकर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का पालन करे।

मानव अधिकारों का पालन करना:

- एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सभी प्रकार के शरणार्थियों के लिए शरणार्थी-स्थिति निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों की गारंटी देगा।

सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना:

- यह भारत की सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की आड़ में कोई गैरकानूनी हिरासत या निर्वासन नहीं किया गया है।

शरणार्थियों के साथ व्यवहार में असंगति:

- भारत में शरणार्थी आबादी का बड़ा हिस्सा श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अफगानिस्तान से आता है।
- हालांकि, सरकार द्वारा केवल तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को ही इस रूप में मान्यता दी गई है।
- उन्हें सरकार द्वारा तैयार की गई विशिष्ट नीतियों और नियमों के माध्यम से सीधे सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाती है।

फ्लोर टेस्ट/ शक्ति परीक्षण

प्रसंग :

- बिहार में नई महागठबंधन सरकार ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया है।

फ्लोर टेस्ट/ शक्ति परीक्षण के बारे में:

- शक्ति परीक्षण मुख्य रूप से यह जानने के लिए लिया जाता है कि कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास प्राप्त है या नहीं।
- यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में होता है।
- यह एक संवैधानिक तंत्र है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति:

- संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- जब एक दल सदन में बहुमत प्राप्त करता है, तो राज्यपाल दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

विश्वास मत:

- यदि बहुमत पर सवाल उठाया जाता है, तो बहुमत का दावा करने वाले दल के नेता को विश्वास मत लाना होगा और उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के बीच बहुमत साबित करना होगा।
- वोट भौतिक मतदान के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र के माध्यम से लिया जाता है

अविश्वास प्रस्ताव: अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जो लोकसभा में पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अब किसी भी तरह से उनकी अपर्याप्तता या उनके अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण जिम्मेदारी के पदों को संभालने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। लोकसभा में इसे अपनाने के लिए कोई पूर्व कारण बताए जाने की आवश्यकता नहीं है।

बहुमत साबित करने में विफल रहने पर क्या होगा?

- मौजूदा मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने में विफल रहने पर इस्तीफा देना पड़ता है।
- सरकार बनाना:
 - इस स्थिति में विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है।
 - राज्यपाल तब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को अपना बहुमत साबित करने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
- यदि यह नवनिर्वाचित सरकार है:
 - यदि यह एक नवनिर्वाचित सरकार है, तो सदन की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है, जिसे राज्यपाल द्वारा चुना जाता है।

प्रोटेम स्पीकर :

- प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है।
- उसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यों के संचालन के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
- नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।

कर्तव्य:

- प्रोटेम स्पीकर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तथा नव निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पद की शपथ दिलाते हैं।
- स्पीकर का चुनाव करवाता है।
- नए अध्यक्ष/स्पीकर के चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।

इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175(2):**
 - यह राज्यपाल को विधानसभा को आहूत करने और बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान करने की शक्ति देता है कि क्या राज्य विधानसभा में मौजूदा सरकार के पास बहुमत है।
 - केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164:**
 - इसमें कहा गया है कि, “मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।”
 - और इसलिए, यदि उन्हें विधायिका का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो कार्यपालिका को पद छोड़ना होगा।
- **एस.आर. बोम्मई मामले:**
 - इस ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री के फ्लोर टेस्ट से इनकार करने को सरकार का विधायिका का विश्वास खोने के रूप में माना जाएगा।



अभ्यास प्रश्न

1. गलत कथन चुनें:

- GEO उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) जीटीओ कक्षा का उपयोग करता है।
- LEO में रखे गए उपग्रह का तल झुका हुआ हो सकता है।
- SSO उपग्रह पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- एनडीएमए अधिनियम समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए आपदा प्रबंधन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।
- यह अधिनियम राज्य और जिला स्तर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनाएँ बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- हंबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी सिरे में गहरे पानी का बंदरगाह है।
- इसका निर्माण श्रीलंकाई बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा किया गया है और ज्यादातर ब्रिक्स द्वारा वित्त पोषित है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- रोहिंग्या, एक जातीय समूह है जिसमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत से हैं।
- भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्षधर है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कारण बताया जाना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि, “मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।”

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

उत्तर

1	2	3	4	5
B	B	D	A	D

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।